प्रस्ताव क्रमांक १

“बांग्लादेश में मानवता पर हो रहे अत्याचार तुरंत बंद हों”

विगत 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में तख्तापलट के दुष्चक्र के पश्चात वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हुए जघन्य पाशविक अत्याचार, लूट-पाट एक पूर्व नियोजित सोची-समझी वैदेशिक षडयन्त्र का ही परिणाम था |

विद्यार्थियों के आंदोलन को बहुत ही जल्दी, पहले से घात लगाई चरमपंथी ताकतों ने इसे कब्जा (Hijack) कर लिया और वहाँ की प्रधानमंत्री बेगम शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा तथा उन्हे देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनके देश छोड़ते ही राजधानी ढाका में तथा देश के अनेक हिस्सों में अराजकता फैल गई।

बांग्लादेश में हजारों वर्षों से रह रहे वहाँ के मूल समाज के लोगों को निशाना बनाते हुए हैवानियत की सारी हदे पार कर दी गयीं। राजधानी में हजारों निरीह स्त्री,पुरुष एवं बच्चों तक को बर्बरता से मारा गया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ। दुराचारियों की इस हिंसक प्रवृति ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया.।

बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक विरासत को गहरा आघात लगा है। बांग्लादेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, देश में चलने वाले वस्त्र, जूट एवं अन्य उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और हजारों मजदूर बेरोजगार हुए हैं। वहाँ के हिंदू -बौद्ध तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय में अभी भी भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। उनके वीभत्स उत्पीड़न की घटनाएं जो सोशल मीडिया व अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचारित हुई है, उन अमानवीय घटनाओं को देखकर दिल दहल जाता है। यह मानवाधिकारों का खुला हनन है, जो सर्वदूर निंदनीय है।

इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की चुप्पी भी एक गहरा संदेह पैदा करती है | इन सभी परिस्थितियों को ठीक करने और वहाँ के इन अल्पसंख्यक समाज के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बांग्लादेशवासियों की ही है.।

ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश सहित संपूर्ण विश्व समुदाय वहाँ के पीड़ित समाज के साथ खड़े हों तथा गहरी संवेदना के साथ उनके हिम्मत और आत्मविश्वास को जगाए।

15 अगस्त के महोत्सव को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में चिंता व्यक्त की है तथा कहा कि “बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी

देश के नाते चिंता होना मैं समझ सकता सकता हूं, वहां के हिंदू एवं अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो l मैं आशा करता हूं कि वहाँ पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे."

अतः भारतीय मजदूर संघ की 157 वीं विस्तारित केंद्रीय कार्यसमिति सर्वसम्मति से इस कुकृत्य की घोर निंदा करती है तथा भारत सरकार से यह मांग करती है कि बांग्लादेश के अंदर हो रहे अत्याचारों को तुरंत बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, जिससे वहाँ का जन जीवन सामान्य हो सके तथा वहाँ शांति बहाल हो l

प्रस्तावक : श्री अनुपमजी

अनुमोदक : 1) श्री .विराज टीकेकर

2) श्री सोमश विश्वास